भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2883

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

छत्तीसगढ़ में बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्यक्रम

2883. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रम के कार्यान्वयन में चूक रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी चूक के प्रकार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छत्तीसगढ़ के लिए उक्त अवधि के दौरान कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई;

(घ) उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटित निधि के दुरुपयोग से संबंधित सूचित की गई घटनाएं, जिनके परिणामस्वरूप अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके, क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ में ऐसी अनियमितताओं की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच दल भेजने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच का दायरा क्या है तथा इसके संभावित परिणाम क्या होंगे?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन सहित उसे आबंटित की गई धनराशि के दुरुपयोग से संबंधित घटनाओं के बारे में पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उक्त अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा राज्य को बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की गई है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) और पारी-पासू कमान क्षेत्र विकास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की तीन परियोजनाओं को शामिल किया गया है। दो परियोजनाओं नामत मनियारी टैंक परियोजना और खारुंग परियोजना के एआईबीपी घटक का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि केलो परियोजना चल रही है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ को 49.62 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, केलो सिंचाई परियोजना को 40.633 करोड़ रुपये, मनियारी टैंक को 43.57 करोड़ रुपये और वर्ष 2016 से पहले (वर्ष 2008-09 से वर्ष 2015-16 के दौरान) खारुंग परियोजना को 10.47 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

सभी तीनों परियोजनाओं के कमान क्षेत्र विकास-जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) घटक नामतः मनियारी टैंक परियोजना, खारुंग परियोजना और केलो परियोजना चल रहे हैं और वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ को 28.58 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

(ङ) और (च): भाग (क) से (घ) के उत्तर के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में अनियमितताओं की जांच करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण दल भेजने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****